Sector: Agriculture and AgriTech and Investment Promotion.

Topic :- Rajasthan to exhibit Agricultural Innovation at GRAM-2026 Roadshow in New Delhi.

Introduction

The roadshow of Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)-2026 will be held on 23 April 2026, at Convention Hall, Hotel The Ashok, New Delhi. The event will be a significant move towards making Rajasthan a major hub of agricultural innovation and investment. It seeks to project the progressive agricultural policies, investment potential and opportunities that exist in agriculture and allied industries in the state in front of national and international stakeholders. The roadshow will also help foster meaningful collaboration with industries, startups, and academic institutions, which will further empower the transformation of agriculture in Rajasthan and put in place a more robust platform of innovation-led growth.

The most important details of the Roadshow are as follows.

- The roadshow will be held on 23 April 2026 in New Delhi.
- It is also being planned to speed up the preparations of the GRAM–2026.
- The programme will emphasize the agro policy and investment opportunities of Rajasthan.
- It will target at agritech, agriculture and related industries.
- The event aims at facilitating innovation, investment and strategic alliances in the state.

Participation and Stakeholders

The roadshow will engage a vast number of stakeholders related to agriculture and agritech. These comprise of policy guides, policymakers, industrialists, entrepreneurs, agritech startups, Farmer Producer Organisations (FPOs) and progressive farmers. Their involvement is important since it establishes a shared ground of discourse among the government, the private sector, research institutes and the farming communities. This kind of interaction can be used to find viable solutions, investment opportunities and partnering opportunities in the future development of the agricultural industry in Rajasthan.

The areas of discussion include:

Industry representatives will have special sessions during the roadshow where they will share their experiences and ideas. The agritech area and the best practices application will be discussed in terms of innovation. The programme will also shed light on the strategy and vision of Rajasthan on how it plans to transform its agricultural sector. Moreover, discussions with key businesses, startups and academicians will be conducted on potential areas of

RASonly

collaboration within the state. This renders the event significant as a marketing platform as well as a policy and partnership-making exercise.

The importance of the Roadshow

The analysis wise, this is a significant development since it indicates how Rajasthan has been trying to improve its agriculture by use of technology, investing and institutional co-operation. It also demonstrates the increase in the contribution of agritech, startups, and organised farmer groups to the development of agriculture. The roadshow may be regarded as the larger initiative of linking governance, personal investment, and innovation to enhance productivity and competitiveness in agriculture. On this note, the event is a big administrative and economic project to the state.

Conclusion

The roadshow of the Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)2026 is a major initiative to give Rajasthan a boost in the sphere of agricultural innovation and investment. It will unite policymakers, industry leaders, startups, farmers, and academic institutions and is likely to introduce new areas of collaboration and jumpstart the agricultural change in the state.

MCQs

1. What is the venue of the roadshow of Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)-2026, taking place on 23 April 2026?

A. Jaipur Exhibition Centre.

B. Convention Hall, Hotel The Ashok, New Delhi

C. Vigyan Bhawan, New Delhi.

D. Rajasthan International Centre, Jaipur

Answer: B

Explanation : Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM)- 2026 roadshow will be held on 23 April 2026, at the Convention Hall, Hotel The Ashok, New Delhi. The venue is significant as the event will showcase the agricultural potential of Rajasthan and will be able to attract the participation of more stakeholders both national and international.

2. What is the overall purpose of the GRAM-2026 roadshow?

A. To give farm subsidies to farmers.

B. To carry out crop buying activities.

C. To introduce the agricultural policies, investment potential and opportunities in agriculture and allied sector in Rajasthan.

RASonly

D. To declare a new irrigation census.

Answer: C

Explanation : The primary goal of the road show is to present the progressive agricultural policies, investment opportunities in Rajasthan and the possibilities in agriculture and allied sector in a larger stage. It is also meant to promote collaborations with industries, startups, and higher education institutions, and thus a significant project in agricultural transformation.

3. Which of the following groups is specifically targeted to attend the GRAM2026 roadshow?

A. Ministers of the government and judges only.

B. Only agricultural labour unions

C. Policy makers, industrialists, entrepreneurs, agritech startups, FPOs, and progressive farmers.

D. Only international trade delegations

Answer: C

Explanation: The event will be a multi-stakeholder platform. Based on the provided information, policy guides, policymakers, industrialists, entrepreneurs, agritech startups, Farmer Producer Organisations (FPOs), and progressive farmers will be included. This widespread involvement is indicative of the government trying to encourage cooperation and innovation within the agricultural sector in Rajasthan.

क्षेत्र: कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी और निवेश प्रोत्साहन

विषय: नई दिल्ली में ग्राम-2026 रोडशो के माध्यम से राजस्थान कृषि नवाचार का प्रदर्शन करेगा

परिचय

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 का रोडशो 23 अप्रैल 2026 को कन्वेंशन हॉल, होटल द अशोक, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रगतिशील कृषि नीतियों, निवेश क्षमता तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हितधारकों के समक्ष प्रस्तुत करना है। यह रोडशो उद्योगों, नवप्रवर्तक उद्यमों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सार्थक

RASonly

सहयोग को भी बढ़ावा देगा, जिससे राजस्थान में कृषि परिवर्तन को नई गति मिलेगी और नवाचार-आधारित विकास के लिए एक मजबूत मंच तैयार होगा।

रोडशो की प्रमुख विशेषताएँ

- रोडशो 23 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।
- इसका आयोजन ग्राम-2026 की तैयारियों को गति देने के लिए किया जा रहा है।
- कार्यक्रम में राजस्थान की कृषि नीतियों और निवेश अवसरों को प्रमुखता दी जाएगी।
- इसका केंद्र कृषि, कृषि-प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्र होंगे।
- यह आयोजन राज्य में नवाचार, निवेश और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।

भागीदारी और हितधारक

इस रोडशो में कृषि और कृषि-प्रौद्योगिकी से जुड़े अनेक हितधारक भाग लेंगे। इनमें नीति मार्गदर्शक, नीति-निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी, कृषि-प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्रगतिशील किसान शामिल होंगे। इनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकार, निजी क्षेत्र, अनुसंधान संस्थानों और कृषक समुदाय के बीच संवाद का एक साझा मंच तैयार होगा। इस प्रकार की सहभागिता राजस्थान के कृषि क्षेत्र के भविष्य के विकास के लिए व्यावहारिक समाधान, निवेश संभावनाएँ और सहयोग के अवसरों की पहचान करने में सहायक हो सकती है।

चर्चा के प्रमुख क्षेत्र

रोडशो के दौरान उद्योग प्रतिनिधियों के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें वे अपने अनुभव और विचार साझा करेंगे। इन चर्चाओं में कृषि-प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार और श्रेष्ठ कार्य-पद्धतियों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कार्यक्रम राजस्थान की कृषि व्यवस्था में परिवर्तन लाने की रणनीति और दृष्टि पर भी प्रकाश डालेगा। इसके अतिरिक्त, प्रमुख कंपनियों, नवप्रवर्तक उद्यमों और शिक्षाविदों के साथ राज्य में संभावित सहयोग के क्षेत्रों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। इस प्रकार यह आयोजन केवल एक प्रचार मंच ही नहीं, बल्कि नीति-निर्माण और साझेदारी निर्माण का भी महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।

रोडशो का महत्व

RASonly

परीक्षा की दृष्टि से यह विकास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि राजस्थान प्रौद्योगिकी, निवेश और संस्थागत सहयोग के माध्यम से अपनी कृषि व्यवस्था को आधुनिक बनाने का प्रयास कर रहा है। यह कृषि विकास में कृषि-प्रौद्योगिकी, नवप्रवर्तक उद्यमों और संगठित किसान समूहों की बढ़ती भूमिका को भी स्पष्ट करता है। इस रोडशो को शासन, निजी निवेश और नवाचार को जोड़ने वाली एक व्यापक पहल के रूप में देखा जा सकता है, जिसका उद्देश्य कृषि में उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। इस दृष्टि से यह राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और आर्थिक पहल है।

निष्कर्ष

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 का रोडशो राजस्थान को कृषि नवाचार और निवेश के क्षेत्र में नई पहचान देने वाली एक प्रमुख पहल है। यह नीति-निर्माताओं, उद्योग जगत, नवप्रवर्तक उद्यमों, किसानों और शैक्षणिक संस्थानों को एक मंच पर लाकर सहयोग के नए अवसर उत्पन्न करेगा तथा राज्य में कृषि परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. 23 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 रोडशो का आयोजन स्थल क्या है?

A. जयपुर प्रदर्शनी केंद्र

B. कन्वेंशन हॉल, होटल द अशोक, नई दिल्ली

C. विज्ञान भवन, नई दिल्ली

D. राजस्थान अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जयपुर

उत्तर: B

व्याख्या: ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 का रोडशो 23 अप्रैल 2026 को कन्वेंशन हॉल, होटल द अशोक, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह स्थल महत्वपूर्ण है क्योंकि इस कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान की कृषि क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी।

2. ग्राम-2026 रोडशो का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. किसानों को प्रत्यक्ष कृषि अनुदान देना

B. फसल क्रय गतिविधियाँ संचालित करना

RASonly

C. राजस्थान की कृषि नीतियों, निवेश क्षमता तथा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को प्रस्तुत करना

D. नई सिंचाई जनगणना की घोषणा करना

उत्तर: C

व्याख्या: रोडशो का मुख्य उद्देश्य राजस्थान की प्रगतिशील कृषि नीतियों, निवेश क्षमता और कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों को व्यापक मंच पर प्रस्तुत करना है। यह उद्योगों, नवप्रवर्तक उद्यमों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग को भी बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है, जिससे कृषि परिवर्तन को नई दिशा मिल सके।

3. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह विशेष रूप से ग्राम-2026 रोडशो में भाग लेने के लिए लक्षित है?

A. केवल सरकारी मंत्री और न्यायाधीश

B. केवल कृषि श्रमिक संगठन

C. नीति-निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी, कृषि-प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्रगतिशील किसान

D. केवल अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल

उत्तर: C

व्याख्या: यह आयोजन बहु-हितधारक मंच के रूप में तैयार किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इसमें नीति मार्गदर्शक, नीति-निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी, कृषि-प्रौद्योगिकी नवप्रवर्तक उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्रगतिशील किसान भाग लेंगे। यह व्यापक भागीदारी राज्य के कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और निवेश को प्रोत्साहित करने की सरकारी मंशा को दर्शाती है।

RASonly

RASonly

Sector: Agriculture, Biotechnology and Seed Regulation.

Topic: Bt Cotton Hybrid Seeds Sale Allowed in Rajasthan in Kharif 2026.

Introduction

The Rajasthan government has officially authorized the sale of Bt cotton hybrid seeds of Kharif 2026 to commercially grow non-modified (BG-II, GFM) Bt cotton hybrids. It has been decided as per the suggestions of the recommendation of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Standing Committee on Bt Cotton. Under this scheme, the supply of Bt cotton hybrid seeds to various agro-climatic areas of the state will be permitted to 34 approved seed companies under prescribed conditions. The significance of the move is that it incorporates the agricultural productivity, regulation of biotechnology, quality control of seed, training and control of farmers and regional diseases.

Significant Characteristics of the Permission

- Kharif 2026: Rajasthan has given a formal permission of selling Bt cotton hybrid seeds.
- The authorization is on non-modified (BG-II, GFM) Bt cotton hybrids.
- The permission is granted according to the proposals of the GEAC and Standing Committee on Bt Cotton.
- There will be 34 approved seed companies who will supply seeds in various agro-climatic areas in the state.

- Supply will be permitted on condition of specified regulatory conditions.

The Performance Testing and Regional Permission

According to the Agriculture Commissioner, Naresh Kumar Goyal, the success of every hybrid of Bt cotton will be tested by compulsory testing on ATC, ARS and KVK farms based on agro-climatic regions. Seed companies are allowed to sell the seeds to the Joint Director Agriculture (ATC), Agriculture Commissionerate until the date of 30 April 2026 and the department would receive testing charges according to the prescribed norms. Once one of the hybrids has already been subjected to a performance test running continuously during a span of two years, then it will not be necessary to conduct additional testing. This is a provision to ensure that scientific assessment is upheld but repetition is not done unnecessarily in the approval process.

Western Districts Disease-Based Restriction

There is a clear ban on the sale of Bt cotton hybrids prone to whitefly and Cotton Leaf Curl Virus (CLCuD) in the west of Sri Ganganagar, Hanumangarh and Bikaner. This is to avoid an outbreak of pest and disease issues in susceptible cotton-producing areas. The ruling is a reminder of a regional regulatory solution to seed distribution and emphasizes the significance of seed suitability and agro-climatic and plant health considerations.

Farmer Training and Cultivation Guidelines

With the help of the Agriculture Department in their sales regions, all seed companies will be required to offer farmers three-stage training. The steps involved in this training will be the phases of pre-sowing, crop growth and harvesting. It will entail adherence to the recommended percentage of Bt structure of refusal seed- 20% of area or five rows of the border with fertilizer and manure management and narrow biological control methods. There should also be a Hindi package of agricultural practices that should be provided with each seed packet to every buyer. This will be to encourage knowledge-based agriculture and enhance adherence to suggested practices of cultivation.

Price Control, QR Code Check and Tracking

Every company has been advised to make sure that the sale price of Bt cotton hybrid seeds of Kharif 2026 does not surpass the minimum-maximum rates announced by the Central Government under the Essential Commodities Act of 1955 as well as the Seeds Control Order of 1983. Every seed packet should have a unique QR code in it to be checked and a valid contact number. The companies will be also required to submit periodically the district-wise sales plans, dealer lists and monthly reports of actual sales to the Joint Director Agriculture (Extension), Zila Parishad, as well as, Agriculture Commissionerate, Jaipur. The department will constantly check the composition of seed quantity and quality of refuge seed.

RASonly

Preference to the Cooperative Sector and Post- release Oversight

The state government has instructed that the priority in the allocation of 15-20 percent in the supply of Bt cotton hybrid seeds in the districts should be provided to the cooperative sector which includes KVSS, GSS and FPOs. This is to make seeds accessible to the small and marginal farmers easily. To this end, it will organize joint meetings between the district administration and Agriculture Department and other Bt cotton companies. Bt cotton will be monitored by committees of the respective regional and departmental, ATCs after release and reports will be analysed at the state level to make policy decisions on the future.

This is an important development that should be discussed

The decision is significant in terms of examination since it unites the problems of agricultural biotechnology, regulatory approval, seed pricing, plant protection, farmer awareness, and cooperative distribution systems. It also demonstrates how the agricultural administration at the state level relies on testing, region specific restriction, training requirements and monitoring provisions to guarantee not only productivity, but also safety of commercial seed use.

Conclusion

This is an important administrative move towards regulated agricultural biotechnology as Bt cotton hybrid seed sale in Rajasthan Kharif 2026 is given the go-ahead. Through integration of scientific testing, disease restrictions, farmer training, price control, cooperative access and post-release monitoring, the state has developed a well designed system of seed distribution and cotton cultivation management.

MCQs

1. What is the name of the body on the basis of which the Rajasthan government has authorized the sale of Bt cotton hybrid seeds on Kharif 2026?

A. NITI Aayog and ICAR.

B. GEAC and Standing Committee on Bt Cotton.

C. NABARD and FCI

D. CACP and Agricultural Costs Commission.

Answer: B

Explanation: Bt cotton hybrid seeds Kharif 2026 have been approved to be sold under the recommendations of the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and the Standing Committee on Bt

RASonly

Cotton. This renders option B right. The other institutions mentioned are not approving bodies as they are in this case.

2. Which district(s) has banned the sale of Bt cotton hybrids prone to whitefly and Cotton Leaf Curl Virus (CLCuD) in Rajasthan?

A. Udaipur, Chittorgarh and Rajsamand

B. Kota, Bundi and Baran

C. Sri Ganganagar, Hanumangarh and Bikaner.

D. Jaipur, Alwar and Sikar

Answer: C

Explanation : Bt cotton hybrids prone to whitefly and Cotton Leaf Curl Virus have been specially banned in the western regions of Sri Ganganagar, Hanumangarh and Bikaner by Rajasthan. This limitation is supposed to curb outbreak of diseases in susceptible cotton growing regions. As such, option C is right, and the other district groups are not subjected to this restriction.

3. Which among the following is true in terms of training and distribution of Bt cotton hybrid seeds in Rajasthan in Kharif 2026?

A. Farmers will be trained just at the harvesting level.

B. Seed packets do not have to be authenticated.

C. Cooperative institutions priority has been assigned 15-20% allocation in the supply of districts.

D. Refuge seed use has been completely removed from the cultivation protocol.

Answer: C

Explanation: The state government has given a priority to allocate 15-20% of the total amount of supply to the cooperative sector, such as KVSS, GSS and FPOs, at the district level to ensure that small and marginal farmers have easier access to seeds. The training will be provided in three phases, the seed packets will have a QR code, and compliance with refuge seed will also be required. Hence, option C is the correct statement.

क्षेत्र: कृषि, जैव-प्रौद्योगिकी और बीज विनियमन

विषय: राजस्थान में खरीफ 2026 हेतु बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को अनुमति

परिचय

RASonly

राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 के लिए गैर-संशोधित (बीजी-II, जीएफएम) बीटी कपास हाइब्रिड की व्यवसायिक खेती हेतु बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री को औपचारिक स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति तथा बीटी कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राज्य के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में निर्धारित शर्तों के अनुसार 34 अनुमोदित बीज कंपनियों को बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की आपूर्ति की अनुमति दी गई है। यह निर्णय कृषि उत्पादकता, जैव-प्रौद्योगिकी विनियमन, बीज गुणवत्ता नियंत्रण, किसान प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय रोग प्रबंधन को एक साथ जोड़ता है।

अनुमति की प्रमुख विशेषताएँ

- राजस्थान ने खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की औपचारिक अनुमति जारी की है।
- यह अनुमति गैर-संशोधित (बीजी-II, जीएफएम) बीटी कपास हाइब्रिड पर लागू है।
- स्वीकृति जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति तथा बीटी कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार प्रदान की गई है।
- 34 अनुमोदित बीज कंपनियाँ राज्य के विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बीजों की आपूर्ति कर सकेंगी।
- आपूर्ति केवल निर्धारित विनियामक शर्तों के अंतर्गत ही की जाएगी।

प्रदर्शन परीक्षण और क्षेत्रीय अनुमति

कृषि आयुक्त श्री नरेश कुमार गोयल के अनुसार प्रत्येक बीटी कपास हाइब्रिड के प्रदर्शन का मूल्यांकन कृषि-जलवायु क्षेत्रवार एटीसी, एआरएस और केवीके फार्मों पर अनिवार्य परीक्षण के माध्यम से किया जाएगा। बीज कंपनियाँ 30 अप्रैल 2026 तक संयुक्त निदेशक कृषि (एटीसी), कृषि आयुक्तालय को बीज उपलब्ध करा सकती हैं और विभाग निर्धारित मानकों के अनुसार परीक्षण शुल्क प्राप्त करेगा। यदि किसी हाइब्रिड पर लगातार दो वर्षों तक प्रदर्शन परीक्षण हो चुका है, तो अतिरिक्त परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। यह प्रावधान वैज्ञानिक मूल्यांकन को बनाए रखते हुए अनावश्यक पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया गया है।

RASonly

पश्चिमी जिलों में रोग-आधारित प्रतिबंध

राजस्थान ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में सफेद मक्खी तथा कॉटन लीफ कर्ल वायरस के प्रति संवेदनशील बीटी कपास हाइब्रिड की बिक्री पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया है। इसका उद्देश्य संवेदनशील कपास उत्पादक क्षेत्रों में कीट और रोग प्रकोप को रोकना है। यह निर्णय दर्शाता है कि बीज वितरण में क्षेत्र-विशिष्ट विनियमन अपनाया जा रहा है और बीज उपयुक्तता को कृषि-जलवायु तथा पादप स्वास्थ्य स्थितियों के अनुरूप महत्व दिया जा रहा है।

किसान प्रशिक्षण और कृषि पद्धति दिशा-निर्देश

सभी बीज कंपनियों को कृषि विभाग के सहयोग से अपने बिक्री क्षेत्रों में किसानों को त्रि-स्तरीय प्रशिक्षण देना होगा। यह प्रशिक्षण बुवाई-पूर्व, फसल-वृद्धि और कटाई के चरणों को शामिल करेगा। इसमें बीटी संरचना वाले रिफ्यूज बीज के निर्धारित अनुपात का पालन, अर्थात 20% क्षेत्र या पाँच सीमावर्ती कतारें, उर्वरक एवं खाद प्रबंधन तथा संकीर्ण जैव-नियंत्रण तकनीकों का समावेश होगा। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ग्राहक को प्रत्येक बीज पैकेट के साथ हिंदी में तैयार कृषि पद्धतियों का पैकेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य ज्ञान-आधारित खेती को बढ़ावा देना और अनुशंसित कृषि पद्धतियों के पालन को सुदृढ़ करना है।

मूल्य नियंत्रण, क्यूआर कोड सत्यापन और निगरानी

सभी कंपनियों को निर्देश दिया गया है कि खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री कीमत केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 के अंतर्गत अधिसूचित न्यूनतम-अधिकतम दरों से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक बीज पैकेट पर सत्यापन हेतु एक अद्वितीय क्यूआर कोड तथा एक वैध संपर्क संख्या अंकित होना अनिवार्य है। कंपनियों को जिला-वार बिक्री योजना, विक्रेता-सूची तथा वास्तविक बिक्री की पखवाड़े-आधारित रिपोर्ट नियमित रूप से संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद तथा कृषि आयुक्तालय, जयपुर को उपलब्ध करानी होगी। विभाग बीज की मात्रा संरचना तथा रिफ्यूज बीज की गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करेगा।

सहकारी क्षेत्र को प्राथमिकता और जारीकरण के बाद निगरानी

RASonly

राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की जिला-स्तरीय आपूर्ति में 15-20% आवंटन प्राथमिकता सहकारी क्षेत्र को दी जाए, जिसमें केवीएसएस, जीएसएस और किसान उत्पादक संगठन शामिल हैं। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को बीजों की सरल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और संबंधित बीटी कपास कंपनियों के बीच संयुक्त बैठकें आयोजित की जाएंगी। बीज जारी होने के बाद संबंधित क्षेत्रीय तथा विभागीय एटीसी की समितियाँ बीटी कपास की निगरानी करेंगी और उनकी रिपोर्टों का राज्य स्तर पर विश्लेषण भविष्य के नीतिगत निर्णयों के लिए किया जाएगा।

यह विकास क्यों महत्वपूर्ण है

परीक्षा की दृष्टि से यह निर्णय महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कृषि जैव-प्रौद्योगिकी, विनियामक स्वीकृति, बीज मूल्य निर्धारण, पादप संरक्षण, किसान जागरूकता तथा सहकारी वितरण प्रणाली जैसे विषयों को एक साथ जोड़ता है। यह भी स्पष्ट करता है कि राज्य स्तरीय कृषि प्रशासन व्यावसायिक बीज उपयोग में उत्पादकता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण, क्षेत्र-विशिष्ट प्रतिबंध, प्रशिक्षण आवश्यकताओं और निगरानी व्यवस्थाओं का उपयोग करता है।

निष्कर्ष

राजस्थान में खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति विनियमित कृषि जैव-प्रौद्योगिकी की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है। वैज्ञानिक परीक्षण, रोग-आधारित प्रतिबंध, किसान प्रशिक्षण, मूल्य नियंत्रण, सहकारी पहुँच और जारीकरण के बाद निगरानी को एकीकृत करके राज्य ने बीज वितरण और कपास खेती प्रबंधन की एक सुव्यवस्थित रूपरेखा विकसित की है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. राजस्थान सरकार ने खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति किन निकायों की सिफारिशों के आधार पर दी है?

A. नीति आयोग और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद

B. जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति और बीटी कपास पर स्थायी समिति

C. नाबार्ड और भारतीय खाद्य निगम

D. कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और कृषि लागत आयोग

RASonly

उत्तर: B

व्याख्या: खरीफ 2026 के लिए बीटी कपास हाइब्रिड बीजों की बिक्री की अनुमति भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जेनेटिक इंजियरिंग मूल्यांकन समिति तथा बीटी कपास पर स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर दी गई है। इसलिए विकल्प B सही है। अन्य संस्थाएँ इस प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्थाएँ नहीं हैं।

2. राजस्थान में सफेद मक्खी और कॉटन लीफ कर्ल वायरस के प्रति संवेदनशील बीटी कपास हाइब्रिड की बिक्री किन जिलों में प्रतिबंधित की गई है?

A. उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद

B. कोटा, बूंदी और बारां

C. श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर

D. जयपुर, अलवर और सीकर

उत्तर: C

व्याख्या: राजस्थान ने विशेष रूप से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर जैसे पश्चिमी जिलों में सफेद मक्खी तथा कॉटन लीफ कर्ल वायरस के प्रति संवेदनशील बीटी कपास हाइब्रिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध रोग प्रकोप को रोकने के लिए लगाया गया है। इसलिए विकल्प C सही है, जबकि अन्य जिलों का इस प्रतिबंध से संबंध नहीं है।

3. खरीफ 2026 में राजस्थान में बीटी कपास हाइब्रिड बीजों के प्रशिक्षण और वितरण ढाँचे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

A. किसानों को केवल कटाई के चरण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

B. बीज पैकेट पर सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

C. सहकारी संस्थाओं को जिला-स्तरीय आपूर्ति में 15-20% आवंटन प्राथमिकता दी गई है।

D. रिफ्यूज बीज के उपयोग को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

उत्तर: C

व्याख्या: राज्य सरकार ने निर्देश दिया है कि जिला-स्तरीय आपूर्ति में 15-20% आवंटन प्राथमिकता सहकारी क्षेत्र, जैसे केवीएसएस, जीएसएस और किसान उत्पादक संगठनों को दी जाए, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को बीज आसानी से उपलब्ध हो सकें। प्रशिक्षण तीन

RASonly

चरणों में दिया जाएगा, बीज पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा, और रिफ्यूज बीज का पालन भी आवश्यक रहेगा। इसलिए विकल्प C सही है ।

Sector: Industry, Worker Welfare and Sports Infrastructure.

Topic: RIICO to build Sports Facility Centres in Industrial Areas of Rajasthan.

Introduction

The Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation will be launching sports facility centres at the chosen industrial locations as a strategy of enhancing the worker wellness, positivity in workplace and overall productivity. The project is to change the industrial areas, which are solely occupied with machinery and production to more balanced places where fitness and recreation can be supported. In this plan, land will be availed in overcrowded industrialized regions where majority of plots are already allocated to build sporting facilities. This move is important in the examination perspective in that it connects industrial development and labour welfare, with the focus of population health, improved work culture and employment oriented infrastructural planning in Rajasthan.

The main characteristics of the Initiative

- RIICO has resolved to offer land to sports amenities in overwhelmed industrial areas.
- The aim is to enhance the health status of the entrepreneurs and the workers and establish a favorable work environment.
- The project will improve work efficiency, and promote a healthier lifestyle.
- Sports infrastructure will as well render industrial areas to be more appealing to the youth and prospective investors.
- Allotment of land will be based on a rental model.

Identified Industrial Areas

RIICO has identified land in 17 industrial areas in Rajasthan to develop sports facility centres. These are: Bagru Chitaroli, Apparel Park and Sitapara Phase III, Jaipur, Bhiwadi Phase II, Karauli industrial area, Indraprastha industrial area, in Kota, Kherda in Sawai Madhopur, Arbuda in Abu Road, SGC Parbatsar in Nagaur, Pali Phase IV, Kishangarh Phase IV, Jhunj This extensive territorial coverage indicates that the program is not designed as a localized effort to only serve a single city but is being contemplated as a larger-scale state-level industrial welfare program.

Facility Provisions Land Use

The plots within these industrial regions that are identified to be developed into sports related areas have been about 1000 to 3000 square metres. RIICO has also allowed that the supporting facilities like refreshments, drinking water and rest rooms be allowed to use 20

RASonly

percent of the plot area (including 10 percent of the covered area). This means that the centres are not just being designed as playgrounds but being designed as working wellness areas which can be used regularly by workers and entrepreneurs.

Wider Significance

The initiative is significant in that it represents a new trend of the industrial planning where employee wellbeing is regarded as the element of productivity and development. RIICO is attempting to make industry healthier by ensuring the availability of sports and fitness facilities in the industrial areas. The project would also raise the interest of the youth in establishing industries and would have a role in the development of new jobs. It is in this regard that it integrates industrial development, and social infrastructure and labour-based governance.

Conclusion

The move by RIICO to set up sports facility centres in industrial areas is an interesting move towards achieving a balance between industrial development and human wellbeing. The initiative can boost productivity, morale and the general appeal of the industrial zones in Rajasthan by enhancing health, recreation and working conditions. It is also indicative of a more inclusive and visionary model of industrial development.

MCQs

1. What is the overall aim of establishing sports facilities centres in the industrial regions by RIICO?

A. To substitute factory-plants with family-villages.

B. To enhance health, positivity and work effectiveness in the workplace.

C. To facilitate tourism in the mining areas.

D. To relocate industries out of Rajasthan.

Answer: B

Explanation: The primary goal of the initiative by RIICO is to enhance the health of entrepreneurs and workers, provide a favorable environment at the workplace and boost the efficiency of work. The plan links industrial infrastructure to wellness and recreation. Thus option B is the right one, and the other options lack the spirit of the purpose of the policy.

2. How will the identified land to be used in sports facilities in RIICO industrial areas be allotted?

A. Permanent transfer of freehold.

RASonly

B. Auction sale model.

C. Rental model

D. Cooperative model of farming.

Answer: C

Explanation: The plots that are to be used in sports facilities within the industrial areas of RIICO will be assigned on a rental basis. This implies that the land is not being sold but put on managed allocation system. This system ensures that the institutions stay in control and at the same time stimulate the growth of sports and wellness facilities in industrial areas.

3.These are some of the statements which one can say is correct about the proposed sports facility centres in RIICO industrial areas:

A. The project has only identified 5 industrial areas.

B. Sports facilities: 1000 to 3000 square metres plots have been identified.

C. There will be no facilities to be built on the land.

D. The initiative is limited only to Jaipur district.

Answer: B

Explanation: The plot size determined by RIICO extends to 17 industrial areas in Rajasthan with a total of approximately 1000 to 3000 square metres to develop sports facilities. The provision of amenities like refreshments, drinking water and rest rooms will also be allowed in a small area of the land. Therefore, option B is accurate whereas the others are not factual.

क्षेत्र: उद्योग, श्रमिक कल्याण और खेल अवसंरचना

शीर्षक: राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों में रीको स्थापित करेगा खेल सुविधा केंद्र

परिचय

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम ने चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधा केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसका उद्देश्य श्रमिकों के स्वास्थ्य, कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण और समग्र उत्पादकता को बढ़ाना है। इस पहल का उद्देश्य उन औद्योगिक क्षेत्रों को, जो अब तक केवल मशीनों और उत्पादन गतिविधियों तक सीमित थे, ऐसे संतुलित कार्यस्थलों में बदलना है जहाँ स्वास्थ्य, व्यायाम और मनोरंजन को भी बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना के अंतर्गत उन संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि

उपलब्ध कराई जाएगी, जहाँ अधिकांश भूखंड पहले ही आवंटित हो चुके हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औद्योगिक विकास को श्रमिक कल्याण, जनस्वास्थ्य, बेहतर कार्य संस्कृति और रोजगारोन्मुख अवसंरचना नियोजन से जोड़ती है।

पहल की प्रमुख विशेषताएँ

- रीको ने संतृप्त औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
- इसका उद्देश्य उद्यमियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना तथा अनुकूल कार्य वातावरण विकसित करना है।
- यह पहल कार्यकुशलता बढ़ाने और स्वस्थ जीवनशैली को प्रोत्साहित करने में सहायक होगी।
- खेल अवसंरचना से औद्योगिक क्षेत्र युवाओं और संभावित निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनेंगे।
- भूमि का आवंटन **किराया मॉडल** के आधार पर किया जाएगा।

चिन्हित औद्योगिक क्षेत्र

रीको ने राजस्थान के **17 औद्योगिक क्षेत्रों** में खेल सुविधा केंद्रों के विकास के लिए भूमि चिन्हित की है। इनमें **बगरू छितरौली, अपैरल पार्क और सीतापुरा तृतीय चरण, जयपुर; भिवाड़ी द्वितीय चरण; करौली औद्योगिक क्षेत्र; कोटा का इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र; सवाई माधोपुर का खेरदा; आबूरोड का अर्बुदा; नागौर का एसजीसी परबतसर; पाली चतुर्थ चरण; किशनगढ़ चतुर्थ चरण; झुंझुनूं द्वितीय चरण; बीकानेर के कारनी एवं बीछवाल; बोरणाड़ा का ईपीआईपी; श्रीगंगानगर का 13 एनएनपी; सीकर का एसकेएस रींगस विस्तार; तथा अजमेर का अजयमेरू पालड़ा** शामिल हैं। यह व्यापक भौगोलिक विस्तार दर्शाता है कि यह कार्यक्रम केवल किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य-स्तरीय औद्योगिक कल्याण पहल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भूमि उपयोग और सुविधाओं की व्यवस्था

इन औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगभग **1000 से 3000 वर्गमीटर** तक के भूखंड चिन्हित किए गए हैं। रीको ने यह भी अनुमति दी है कि सहायक सुविधाओं

RASonly

जैसे अल्पाहार, पेयजल और विश्राम कक्ष के लिए भूखंड के **20 प्रतिशत भाग** का उपयोग किया जा सके, जिसमें **10 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्र** शामिल होगा। इससे स्पष्ट है कि इन केंद्रों को केवल खेल मैदान के रूप में नहीं, बल्कि ऐसे व्यावहारिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है जिनका नियमित उपयोग श्रमिक और उद्यमी कर सकें।

व्यापक महत्व

यह पहल महत्वपूर्ण है क्योंकि यह औद्योगिक नियोजन के एक नए दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिसमें कर्मचारी कल्याण को उत्पादकता और विकास का अभिन्न अंग माना गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में खेल और व्यायाम सुविधाएँ उपलब्ध कराकर रीको एक स्वस्थ औद्योगिक संस्कृति विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह पहल युवाओं की उद्योग स्थापना में रुचि भी बढ़ा सकती है और नए रोजगार अवसरों के सृजन में योगदान दे सकती है। इस प्रकार यह औद्योगिक विकास को सामाजिक अवसंरचना और श्रम-आधारित सुशासन से जोड़ती है।

निष्कर्ष

औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधा केंद्र स्थापित करने का रीको का निर्णय औद्योगिक विकास और मानवीय कल्याण के बीच संतुलन स्थापित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य, मनोरंजन और बेहतर कार्य परिस्थितियों को बढ़ावा देकर यह पहल राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्रों की उत्पादकता, कार्य उत्साह और समग्र आकर्षण को बढ़ा सकती है। यह एक अधिक समावेशी और दूरदर्शी औद्योगिक विकास मॉडल की ओर भी संकेत करती है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधा केंद्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है?

A. कारखानों के स्थान पर आवासीय बस्तियाँ बसाना

B. स्वास्थ्य, कार्यस्थल की सकारात्मकता और कार्यकुशलता बढ़ाना

C. खनन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देना

D. उद्योगों को राजस्थान से बाहर स्थानांतरित करना

उत्तर: B

RASonly

व्याख्या: रीको की इस पहल का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों और श्रमिकों के स्वास्थ्य में सुधार करना, कार्यस्थल पर अनुकूल वातावरण विकसित करना और कार्यकुशलता बढ़ाना है। यह योजना औद्योगिक अवसंरचना को स्वास्थ्य और मनोरंजन से जोड़ती है। इसलिए विकल्प B सही है, जबकि अन्य विकल्प नीति के वास्तविक उद्देश्य को व्यक्त नहीं करते।

2. रीको औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के लिए चिन्हित भूमि का आवंटन किस आधार पर किया जाएगा?

A. स्थायी मुक्त स्वामित्व हस्तांतरण

B. नीलामी विक्रय मॉडल

C. किराया मॉडल

D. सहकारी कृषि मॉडल

उत्तर: C

व्याख्या: रीको औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं हेतु चिन्हित भूखंडों का आवंटन किराया मॉडल के आधार पर किया जाएगा। इसका अर्थ है कि भूमि स्थायी रूप से हस्तांतरित नहीं की जाएगी, बल्कि एक नियंत्रित आवंटन व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएगी। इससे संस्थागत नियंत्रण बना रहेगा और औद्योगिक क्षेत्रों में खेल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

3. रीको औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्तावित खेल सुविधा केंद्रों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

A. इस परियोजना के लिए केवल 5 औद्योगिक क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं।

B. खेल सुविधाओं के लिए लगभग 1000 से 3000 वर्गमीटर तक के भूखंड चिन्हित किए गए हैं।

C. भूमि पर किसी भी प्रकार की सहायक सुविधा की अनुमति नहीं होगी।

D. यह पहल केवल जयपुर जिले तक सीमित है।

उत्तर: B

व्याख्या: रीको ने राजस्थान के 17 औद्योगिक क्षेत्रों में खेल सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 1000 से 3000 वर्गमीटर तक के भूखंड चिन्हित किए हैं। भूमि के सीमित भाग पर

RASonly

अल्पाहार, पेयजल और विश्राम कक्ष जैसी सहायक सुविधाओं की भी अनुमति होगी। इसलिए विकल्प B सही है, जबकि अन्य कथन तथ्यात्मक रूप से गलत हैं।

RASonly

RASonly

RASonly

RASonly